मोदी ने अम्बानी की झोली भरने का नया प्लान तैयार किया

अब उसे हर घर से 500 से 1000 रुपये दिलवाए जाएंगे

गिरीश मालवीय

केबल टीवी उद्योग पर आए गहन संकट के सम्बंध में अब स्थितियां स्पष्ट होती जा रही हैं। ट्राई के नए नियम 29 दिसम्बर से लागू हो रहे हैं। अभी यह नियम था कि फ्री टू एयर चैनल देखने के लिए कोई पैसा उपभोक्ता से वसूला नही जा सकता था। केबल टीवी ऑपरेटर आपको 200 से 250 रु में इसीलिए सर्विस उपलब्ध करा पाता था कि उसे ये चैनल फ्री पड़ते थे।

अब 100 फ्री-टू-एयर चैनल के लिए ग्राहक को 130 रुपये प्रति माह का फिक्स चार्ज देना ही होगा, इसके ऊपर प्रत्येक चैनल के लिए प्रति चैनल 2 से 19 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। ज्यादातर पॉपुलर चैनल देखने के लिए लगभग 15 रुपये प्रति चैनल खर्च करने होंगे, यानी अब आप का केबल का बिल लगभग 450 से 500 रु आएगा। एचडी देखने के लिये तो 700 से 1000 भी खर्च करना पड़ सकते हैं।

अब इसमें जियो का क्या रोल है वह भी समझिए .....

2010 से अनेक डीटीएच ऑपरेटर जैसे वीडियोकॉन, टाटा स्काई आदि केबल और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में उतरे और शहरी उच्च वर्ग और मध्य वर्ग में केबल द्वारा सेवा पहुँचाने का व्यवसाय लगभग खत्म सा हो गया। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में एक वर्ग बच गया जो अभी भी घर में केबल टीवी ऑपरेटर द्वारा बिछाई गई लाइनों से अपना मनोरंजन कर रहा था (खासकर ग्रामीण इलाके)। इस बीच यह इंडस्ट्री भी ऊपरी स्तर पर ऑर्गेनाइज हो गयी थी। लोकल केबल ऑपरेटर्स बड़े एसएमओ से यह चैनल दिखाने की सुविधाएं ले रहे थे। बड़े स्तर केबल टीवी कंपनी को इंडस्ट्री में एसएमओ कहा जाता है। ऐसी कंपनियां ब्रॉडकास्टर्स के साथ कंटेंट और कैरिज डील साइन करती हैं और लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) को सेवाएं देती हैं।

जियो इस खेल मे कैसे एंटर हुआ ? जियो जबसे बनी है उसका एक ही उद्देश्य था कि देश के हर घर से 1000 से 1500 रुपए वसूले। जियो ने मोबाइल जगत में सस्ता डाटा देकर क्रांति कर दी है और अपने लक्ष्य के वह करीब पुहंच रहा है। म उसकी अगली स्टैप हैं जियो की ब्रॉडबैंड सर्विसेस और जिओ की डीटीएच। ये लगभग एक साथ ही मार्केट में आयेंगी।

अब असली खेल समझिए..... बड़ी डीटीएच कम्पनियां तो जियो की आमद से घबरा गई लेकिन उन्हें तो जियो कभी भी खत्म कर सकता है जैसे उसने मोबाइल मार्केट में किया है। उसकी असली समस्या ऑर्गेनाइज सेक्टर नही था, उसकी समस्या ये अनऑर्गेनाइज लोकल केबल ऑपरेटर थे जो छोटे बड़े गाँव कस्बों में जनता को 200 से 250 रु में केबल टीवी की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे।

उसने सबसे पहले बड़े एसएमओ पर हाथ डाला जो इन लोकल केबल ऑपरेटर को यह सुविधा उपलब्ध करा रहे थे। बड़े एसएमओ में दो नाम प्रमुख हैं, रिलायंस ने सबसे पहले इन दोनों कम्पनियों में बड़ा स्टेक खरीदकर इसे अपने मे शामिल कर लिया, ओर बैठे बिठाए अपनी सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले ही रिलायंस इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। अब रिलायंस जियो को हैथवे और डेन नेटवर्क्स के साथ 24 मिलियन ग्राहकों तक सीधे पहुंच मिल चुकी है..... लेकिन जियो गीगा फाइबर जल्दी से लाभ में कैसे आए? उसके लिए सबसे जरूरी है इस इंडस्ट्री में दी जा रही सस्ती सुविधाओं को बंद किये जाना,.... मोदी सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए घर की सरकार है, उसने ट्राई से कहकर फ्री टू एयर वाले चैनल ही बन्द करवा दिए। ब्रॉडकास्टर के रूप में उसके पास नेटवर्क 18 जैसा बड़ा ओर लोकप्रिय चैनलों का बेड़ा था। उसने अन्य सभी चैनलों पर दबाब डाल कर उन्हें पेड कैटेगरी में डाल दिया.....

ट्राई के फ्री चैनलों को पेड किये जाने से लोकल केबल ऑपरेटर इस व्यवसाय में अब टिक ही नही पाएंगे और उन्हें अपना व्यवसाय हैथवे ओर डेन जैसी बड़ी कम्पनियों को सौपना पड़ेगा जो वास्तव में रिलायंस जियो ही है। इस तरह से जियो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन कर उभरेगा ओर आपसे मनोरंजन के नाम पर 500 से 1000 रु हर महीने वसूलेगा ओर आप कहेंगे..... वाह मोदीजी वाह!

48 साल की अजिता जयराजन, एक मेयर यह भी हैं!

त्रिशुर (केरल) की मेयर, और करीब डेढ़ सौ घरों में सुबह सबेरे दूध पहुंचाती हैं. दूध बेचना उनका रोजगार है, रोज की रोटी कमाने का साधन है. इससे उन्हें 10 हजार रुपये महीने कमाई होती है. वह पहले 2005 और उसके बाद 2015 में सभासद बनीं. इस साल बाद केरल के त्रिशुर जिले की मेयर बन गईं. आप अपने इलाके के सभासद से अजिता की तुलना करें. जो करोड़पति का तमगा क्रॉस कर, अरबपति बनने की ओर है. पहली बार जरूर एक बेरोजगार बनकर लोगों की सहानुभूति से सभासद बना था, लेकिन अब वह दारू बांटकर, वोटिंग लिस्ट में फेरबदल करके आराम से जीत लेता है.

अजिता की प्राब्लम यह है कि 1999 में उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की. वह चोर नहीं बन पाईं. दो बार सभासद और इस बार मेयर बनने के बाद भी, उनका मानना है कि उनका रोटी कमाने का माध्यम दूध बेचना ही है, दलाली नहीं.

त्रिशुर कोई छोटा मोटा आम जिला नहीं है, उसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है. यह कम्युनिज्म की ताकत है! नेता कम्युनिटी को साथ लेकर चलता है, न कि चुने जाने के बाद दलाली कर, कम्युनिटी को बेचकर धन जुटाता है.

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 30 दिसम्बर-5 जनवरी 2018 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय ज्वलंत मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में छापा मारकर दस युवकों को गिरफ़्तार और हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद करने का दावा किया कि आईएसआईएस से प्रेरित एक संदिग्ध मॉड्यूल का पर्दाफ़ाश किया है। परन्तु बीबीसी ने गांव वालों के इंटरव्यू करके एक वीडियो के ज़रिए इस झूठ का पर्दाफाश किया, जिसे 'बेगुनाह लड़कों को पकड़ कर किसको उल्लू बना रही है एनआईए...बीबीसी की वीडियो रिपोर्ट ने खोल दी पूरी पोल' में प्रकाशित कर पाठकों को असलियत से रूबरू कराया गया है। एनआईए द्वारा बरामद हथियारों में ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रेशर नोजल को रॉकेट लॉन्चर तथा दिवाली के मौके पर इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखों को बम के रूप में दिखाया गया। एनआईए ने यह भी दावा किया कि गिरफ़्तार किए गये लोग इन जब्त हथियारों और विस्फोटकों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के अधिकारियों तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करने की योजना बना रहे थे टीवी के सभी चैनल मोदी सरकार व एनआइए ने इस दावे का खूब प्रचार किया लेकिन बीबीसी की वीडियो रिपोर्ट को सभी नज़र अंदाज कर गए।

बीबीसी की वीडियो रिपोर्ट के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोग एनआईए के दावों का मजाक उड़ाने लगे तो एनआईए ने अपने समर्थकों में एनआईए के विशेषज्ञों की रिपोर्ट मीडिया में जारी कर दी जिसके अनुसार जब्त किए गए देशी हथियार व विस्फोटक सामग्री (पटाखों) से केवल 40 मिनट में आई ई डी बनाए जा सकते हैं।

स्मरण रहे कि जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मोदी जी पर हमले के षडयंत्र के आरोप में अनेक मुसलमानों को गिरफ़्तार व फ़र्जी एनकाऊंटर कर राज्य में भय व आतंक का वातावरण बना लिया था। अब केन्द्र में भी वहीं प्रक्रिया दोहराई जा रही है। देश में एनआईए तथा अन्य एजेंसियों की दलित, तर्कवादी व प्रगतिशील लोगों तथा मुसलमानों के प्रति संदेहशील सोच प्रभावी है।

केन्द्र में मोदी सरकार द्वारा सत्ता सम्भालने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में आरएसएस और भाजपा कट्टर हिन्दुवादी दबंग लोग सार्वजनिक स्थानों पर मुसलमानों को नमाज पढने पर धमकाते हैं और उन्हें उस स्थान पर इकट्ठा होने से रोकते हैं। विडम्बना है कि प्रशासन भी मुसलमानों की सहायता करने की बजाए उन्हें ही बिना अनुमति प्राप्त किये सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से रोकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है हरियाणा में गुड़गांव तथा उत्तर प्रदेश में नोएडा जहां हाल ही में संघ व भाजपा के दबंगों के दबाव में प्रशासन द्वारा पार्क में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया, जिसकी 'पार्क में नमाज के साथ आरएसएस की शाखा पर बैन क्यों नहीं....गुड़गांव के बाद अब नोएडा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश' में समीक्षा की गई है। जबकि आरएसएस की शाखाएं बिना प्रशासन के अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम लगातार लग रही हैं। वास्तव में संघ व भाजपा के दबंग मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक कर 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र समाज में साम्प्रदायिक तनाव बनाना चाहते हैं।

अरावली संरक्षण क्षेत्र में जंगलात, पर्यावरण तथा खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध निर्माण तथा खनन कार्य लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद में दिल्ली वार्डर से सटे कांत एन्कलेव में बाकायदा सरकार की मंजूरी से वे नक्शा आदि पास करवाकर बनाए गए मकानों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसका 'सुप्रीम कोर्ट का अजब अरावली संरक्षण: कांत एन्कलेव को उजाड़ रही और पंचतारा होटल बनवा रही' में खुलासा किया गया है। इस प्रकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं। पहला, सभी सम्बन्धित विभागों ने कांत एन्कलेव के कॉलेनाईजर को मकान बनाने के लिये वांछित अनुमति पत्र दिए, तव पर्यावरण व अरावली संरक्षण विभाग कहां चले गए थे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के बाद बने मकानों को तोड़ने के आदेश दिए, लेकिन 1992 से पहले बने मकानों को छूट क्यों दी गई ? शायद यहां सुप्रीम कोर्ट के जजों का वर्गहित सामने आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस अहमदी का भव्य मकान कांत एन्कलेव में 1992 से पहले बना था उसे बचाना था।

अरावली संरक्षण क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरी पाबंदी के वावजूद अनखीर-सूरजकुंड रोड पर बेसमेंट सहित बहु मंजली पांच सितारा डिलाईट होटल का निर्माण कार्य धड़ल्ले से लगातार चल रहा है, परन्तु पर्यावरण, वन विभाग, खनन, नगर निगम व अन्य अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, शायद उन्हें सुविधा शुल्क मिल गया होगा। इसके अतिरिक्त, खनन माफिया अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर खनन लगातार कर रहा है। ऐसा प्रतित होता है कि अरावली संरक्षण क्षेत्र में अवैध निर्माण व खनन कार्य के प्रति सभी सम्बन्धित विभाग लाचार व लापरवाह हो रहे हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने-अपने राज्यों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं तथा दोनों राज्यों में बेरोजगारों की तादाद बढती जा रही है। दोनों ही राज्यों में एचसीएस व पीसीएस तथा अन्य पदों के लिये कई वर्षों से परीक्षा ही नहीं हुई है और यदि हुई भी है तो उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिसका 'रोजगार न सही लेकिन युवाओं को सपने दिखाने में माहिर है खट्टर भी' तथा 'हरियाणा ही नहीं सभी राज्य आयोग होड़ लगाए हुए हैं कि कैसे रोजगार ढूंढ रहे युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जाए' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है। हरियाणा में गीता महोत्सव तथा यूपी में कुम्भ में अरबों रुपये लुटाने वाली सरकारों के लिये रोजगार देना उनके एजेंडा पर ही नहीं है। मोदी मीडिया गीता महोत्सव तथा कुम्भ के आयेजन का तो बड़े जोर-शोर से प्रचार करता है लेकिन रोजगार व किसान की बदहाली जैसे मुद्दों को कोई तरजीह नहीं देता।

पांच राज्यों की विधानसभा चुनावों में पराजय से भाजपा निरूत्साहित हो रही थी, लेकिन हरियाणा में पांच नगर निगम चुनाव में विजय से भाजपा व मुख्यमंत्री खट्टर का आत्मविश्वास लौट आया और खट्टर साहेब हर जगह घोषणा कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने निश्चित समय पर ही होंगे, जबकि पहले यह आशंका जतायी जा रही थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। आगामी चुनावों में मोदीजी व खट्टर साहेब की सम्भावित स्थिति का 'हरियाणा विधान सभा चुनाव लोक सभा के साथ-बाद में सरकार तो डूबनी ही है' में मूल्यांकन किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव जीतने के समय से ही हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं और अपना जन सम्पर्क अभियान चालु रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की तरह अपनी सेल्फइमेज को बनाने व पुख्ता करने में लगे रहते हैं, जिसका 'जन सम्पर्क मशीन पर सवार मोदी' में सटीक विश्लेषण किया गया है। मोदी जी हर महीने 'मन की बात' के जरिए जनता से सम्पर्क बनाए हुए हैं और अब अपने साढे चार वर्ष के कार्यकाल के अंत में पहली बार मीडिया को इन्टरव्यू दिया, जिसको सभी चैनल ने प्रसारित किया। लेकिन हैरानी की बात है कि मोदी जी जनता से जुड़े असली मुद्दों की कोई बात नहीं करते।

यूपी के भाजपा विधायक द्वारा हनुमान को मुसलमान बताने पर 'हनुमान जी मुसलमान थे-जल्दी भाग यहां से नहीं तो कौनो आकर बोलेगा...आज जुमा है नमाज पढने नहीं गए', राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक राम बिलास पासवान द्वारा अमितशाह पर सीटों के बटवारे के लिये दबाव डालने पर 'पोलिटिकल वैदर ब्यूरो', नेताओं के कारण जनता की बदहाली पर 'रे युवा....तेरा यह बलिदान, याद रखेगा हिन्दुस्तान', मुख्यमंत्री योगी द्वारा हनुमानल को दलित तथा अन्य भाजपा मन्त्रियों, विधायकों व सांसदों द्वारा विभिन्न जातियों का बताने पर 'जाति प्रमाणपत्र कार्यालय-मिलेगा-मिलेगा, एक-एक कर सबको मिलेगा' तथा संघ परिवार व मोदी सरकार द्वारा इतिहास को संशोधित करने के प्रयास पर 'आपकी गलती नहीं है, नेहरू जी सेलेबस ही गलत बना कर गए हैं' कार्टूनों द्वारा उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।